बीएसएनएल एम्पलॉईज यूनियन

प्रेस वक्तव्य

बीएसएनएलईयू द्वारा साप्ताहिक अभियान।

बीएसएनएल में मुख्य मान्यता प्राप्त यूनियन, बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन (बीएसएनएलईयू) ने 22 मार्च, 2021 से आम जनता के बीच 'सप्ताह भर चलने वाला अभियान' आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह अभियान बीएसएनएल की 4 जी सेवा की तत्काल शुरूआत के लिए और बीएसएनएल के विनिवेश / निजीकरण के खिलाफ लोगों का समर्थन को जुटाने के उद्देश्य से है।

मोदी सरकार बीएसएनएल को 4 जी तकनीक से वंचित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। 23 अक्टूबर, 2019 को मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल को 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने का निर्णय लिया। फैसला होने के बाद लगभग डेढ़ साल बीत गया है। लेकिन, अभी भी बीएसएनएल अपनी 4जी सेवा शुरू करने में असमर्थ है। यह केवल सरकार द्वारा पैदा की गई रुकावटों के कारण है।

मार्च, 2020 में, बीएसएनएल ने 50,000 साइटों की खरीद के लिए एक निविदा मंगाइ थी, ताकि वह 4 जी सेवा शुरू कर सके। लेकिन, सरकार के निर्देशानुसार यह टेंडर रद्द कर दिया गया। इसके बाद, सरकार ने बीएसएनएल को बताया कि, उसे केवल भारतीय निर्माताओं से ही 4 जी कोर उपकरणों की खरीद करनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा भेदभाव है। भारत की अन्य सभी टेलीकॉम कंपनियाँ, एअरटेल, जिओ, वोडाफोन अपने उपकरणों की खरीद केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कर रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी भारतीय कंपनी के पास साबित की हुई 4 जी तकनीक नहीं है। इसके अलावा, किसी भी भारतीय कंपनी के पास बीएसएनएल द्वारा आवश्यक विशाल 4 जी नेटवर्क को स्थापित करने और बनाए रखने की क्षमता नहीं है।

इसलिए, भारतीय विनिर्माण से 4 जी उपकरणों की खरीद के लिए अकेले बीएसएनएल को मजबूर करना, केवल बीएसएनएल को कमजोर करना है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी को निजी हाथों में सौंपना है। इस बीच, बीएसएनएल के खिलाफ एक अभियान भी चलाया गया है कि, सरकार ने बीएसएनएल को पहले ही 4 जी तकनीक, साथ ही पैसा दिया है, लेकिन बीएसएनएल में सुधार नहीं हो रहा है। यह याद किया जा सकता है कि, कर्नाटक के एक भाजपा सांसद श्री अनंतकुमार हेड्गे ने कुछ महीने पहले इसी तरह से बीएसएनएल को बदनाम किया था। इन परिस्थितियों में, बीएसएनएलईयू की मांग है कि, बीएसएनएल को अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण से 4जी उपकरण खरीदने की अनुमति दी जाए।

बीएसएनएल को 4 जी सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं देने के अलावा, सरकार बीएसएनएल के मोबाइल टावरों और ऑप्टिक फाइबर केबल को निजी कंपनियों को सौंपने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपये जुटाने का फैसला किया है। इसमें रेलवे और बीएसएनएल की संपत्ति को बेचकर सरकार ने 1.3 लाख करोड़ रुपये जुटाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल के स्वामित्व वाले मोबाइल टावरों और ऑप्टिक फाइबर की बिक्री के माध्यम से, 40,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए कदम उठा रही है। (स्रोतः टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक 12 मार्च, 2021) बीएसएनएल के मोबाइल टावरों को बेचने का मतलब है, मोदी सरकार का अंतिम लक्ष्य बीएसएनएल का निजीकरण करना है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में बीएसएनएल का अस्तित्व इस देश के लोगों के हित में बहुत आवश्यक है।

इसके अलावा, यह एक त्रासदी है कि, मोदी सरकार भारी लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे एलआईसी, बीपीसीएल, आदि का निजीकरण करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। ये कदम सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भारी संपत्तियों को बड़े कॉरपोरेट्स को सौंपने के लिए उठाए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण, कॉरपोरेट्स द्वारा राष्ट्र के धन को लूटने के अलावा कुछ भी नहीं है।

बीएसएनएलईयू की मांग है कि, बीएसएनएल द्वारा 4जी सेवा शुरू करने में सरकार को अवरोध नहीं बनाने चाहिएं। सरकार को बीएसएनएल के मोबाइल टावरों और ऑप्टिक फाइबर केबल का मुद्रीकरण नहीं करना चाहिए। सरकार को देश की कीमती सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों के निजीकरण के प्रस्ताव को छोड़ देना चाहिए।

******